https://www.jmi.ac.in

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों ने कैंपस की दीवारों पर लिखे आपत्तिजनक नारों की कड़ी निंदा की; विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन मोड अपनाया

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2026

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्टूडेंट्स यूनियन (JMISU) के चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए 18 अक्टूबर, 2026 को विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की सात सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई थी। इस समिति के एक सप्ताह तक चले प्रयासों के बीच, आज सुबह विश्वविद्यालय के अंसारी ऑडिटोरियम लॉन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के 1,500 से अधिक टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के साथ-साथ, जामिया के वाइस-चांसलर प्रो. मजहर आसिफ़ और रजिस्ट्रार प्रो. मो. महताब आलम रिज़वी भी शामिल हुए, ताकि आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सके। यह बैठक चार दौर की बातचीत और कल रात समिति द्वारा छात्रों से अपना प्रदर्शन वापस लेने की अपील के बाद आयोजित की गई थी।

तोड़-फोड़ की घटनाओं और परिसर की दीवारों पर बेहद आपत्तिजनक नारे लिखे जाने पर गहरी नाराज़गी जताते हुए, जामिया के शिक्षकों और कर्मचारियों ने कहा कि ऐसी हरकतें शैक्षणिक माहौल को ख़राब करती हैं और 106 साल के गौरवशाली इतिहास वाले इस संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। बैठक में सर्वसम्मति से दो प्रस्ताव पारित किए गए। पहला, कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे प्रदर्शन स्थल को खाली कर दें और अपना आंदोलन समाप्त करें, ताकि परिसर में शांति हो और सामान्य स्थिति बहाल हो सके। विशेष रूप से 'गालिब स्टेच्यू लॉन' को प्रदर्शनकारी छात्रों ने अवैध रूप से घेर रखा है, जबकि जामिया में विरोध-प्रदर्शन के लिए 'गेट नंबर 18' को निर्धारित किया गया है।

दूसरा, शिक्षकों और कर्मचारियों ने उन दीवारों को फिर से पेंट करवाने का निर्णय लिया जिन्हें खराब कर दिया गया था। उन्होंने उन नारों को बेहद निंदनीय बताया और कहा कि ये देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे नारों से जामिया की प्रतिष्ठा और साख को स्थायी और अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोगों की हरकतों की वजह से एक ऐतिहासिक संस्थान की प्रतिष्ठा खतरे में नहीं डाली जानी चाहिए, खासकर तब जब इसके परिणाम पूरे विश्वविद्यालय समुदाय को प्रभावित कर सकते हों। जामिया में दशकों तक अपनी सेवाएं देने वाले प्रमुख हितधारकों के रूप में, शिक्षकों ने कहा कि वे विश्वविद्यालय को इस तरह बंधक नहीं बनने दे

सकते। उन्होंने सोशल मीडिया पर छात्रों द्वारा फैलाई जा रही झूठी बातों और गलत सूचनाओं पर हैरानी और नाराजगी जताई। इससे संस्थान और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच सकता है।

जामिया के वाइस-चांसलर प्रो. मजहर आसिफ़ और रजिस्ट्रार प्रो. मो. महताब आलम रिज़वी ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने और देश की अखंडता व संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाले आपत्तिजनक नारे लिखने से जामिया की साख को नुकसान पहुँच सकता है। इसका बुरा असर छात्रों की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है, जिससे उनके भविष्य में रोजगार और प्लेसमेंट के अवसरों के साथ-साथ उच्च शिक्षा के मौकों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

बैठक को संबोधित करते हुए, उच्च-स्तरीय समिति के सदस्यों ने कहा कि दो दशक पुराने मुद्दे को सुलझाने के लिए विश्वविद्यालय के त्वरित प्रयासों के बावजूद, प्रदर्शनकारी छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे। हिंसक झड़पों, शिक्षकों पर हमलों और कक्षाओं में बार-बार व्यवधान डालने की घटनाओं के कारण 2006 में जेएमआई छात्र संघ (JMISU) को निलंबित कर दिया गया था। समिति ने बताया कि वर्तमान प्रशासन ने 21 अक्टूबर 2026 को 'JMISU संविधान मसौदा समिति' (JMISU Constitution Draft Committee) के गठन की अधिसूचना जारी की—जोकि एक ऐसी पहल है जो 2006 के बाद से किसी भी वाइस-चांसलर या रजिस्ट्रार ने नहीं की थी। इस कदम के बावजूद, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने प्रशासन के साथ बातचीत करके कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने में कोई रुचि नहीं दिखाई।

समिति के सदस्यों ने दोहराया कि प्रदर्शनकारियों से संपर्क करने के अपने निरंतर प्रयासों के साथ-साथ, विश्वविद्यालय ने 21 अक्टूबर को एक और अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया था कि "12.10.26 से लेकर 21.10.26 को शाम 5:30 बजे तक के कारणों से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ की गई या शुरू की गई सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा की जाएगी।" हालाँकि, इससे भी प्रदर्शनकारी छात्र बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बजाय, छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और समूहों के नेताओं व प्रतिनिधियों को बुलाकर तनाव और बढ़ा दिया। शिक्षकों ने चिंता जताई कि इन घटनाओं से कैंपस का माहौल और खराब हो सकता है, जिससे अराजकता, गुंडागर्दी, तोड़-फोड़ और विश्वविद्यालय की दीवारों को ख़राब किए जाने जैसी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं।

दो प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित करने के बाद, जामिया के टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों ने अंसारी ऑडिटोरियम लॉन से मार्च निकाला। वे गेट नंबर 13 से होते हुए और मुख्य सड़क पार करके गेट नंबर 7 तक पहुँचे। इसके बाद, वे प्रदर्शन स्थल पर गए ताकि छात्रों से बातचीत कर सकें और उन्हें प्रदर्शन समाप्त करने के लिए मना सकें।

छात्रों को विरोध प्रदर्शन खत्म करने और कैंपस में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए मनाने की दो घंटे की कोशिशों के बावजूद, छात्र नारे लगाते रहे। वे लगातार फैकल्टी "go back" के नारे लगा रहे थे। उन्होंने अचानक सुरक्षा गार्डों, स्टाफ और शिक्षकों को धक्का देना शुरू कर दिया। सीनियर फैकल्टी सदस्यों की बार-बार की गई अपील को भी उन्होंने अनसुना कर दिया, जबकि इस हफ्ते की शुरुआत में ही उनकी

मांगें मान ली गई थीं। आखिरकार, शिक्षक और स्टाफ विरोध-प्रदर्शन स्थल से हट गए और अंसारी ऑडिटोरियम वापस चले गए।

दिन भर की इन घटनाओं को देखते हुए, प्रशासन को एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, जिसमें घोषणा की गई कि सभी कोर्सेज की कक्षाएं तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। यह फैसला मौजूदा हालात को देखते हुए और विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ऑनलाइन क्लास के शेड्यूल का पालन करें और कैंपस आने से बचें। जब तक कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं और विश्वविद्यालय की ओर से कोई अगला नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के गेट और लाइब्रेरी बंद रहेंगे।

सीपीआरओ कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया